[Shri Era Sezhiyan]

Government that is there, this is the least that you should consider. And since the Minister is not conceding our request for a judicial inquiry by a Supreme Court Judge, as a mark of protest we stage a walk out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber).

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Some of our friends raised the question whether the *Assam Tribune*, a local English daily, has been publishing some inflammatory statements. It has also come to our notice. Some of these statements published in the *Assam Tribune* are really inflammatory. But it is upto them. This is the situation in the State. Everybody should help us to ease the situation. We appeal to all our Members to speak in such a language that normalcy can be brought there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We now take up Appropriation Bills.

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT BILL, 1983—contd.

THE APPROPRIATION BILL, 1983 —*contd.*

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1983—*contd.*

श्री रामानन्द यादव : यह तो चले गये थे वाक आउट करके। कैसें आकर बोल रहं है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपसभापति महोदय, श्री रामानन्द यादव जी मेरे बोलने पर यह कह रह थे कि हम लोग बहिर्गमन कर गये थे तो फिर आकर कैस बोल रहे हैं। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि यह वही दिल्ली है जिसे किसी जमाने में हस्तिनापुर कहा जाता था। जहां अंधे धृतराष्ट्र को सुपुत्र नाम से संयोधन और कर्म से दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था। उसे भी सुमार्ग पर लाने के लिए कौरव पक्ष के तमाम लोग थक गये थे लेकिन कर्ण शकुनि और अपने भाई दुशासन के कुविचारों के कारण उसने भगवान कृष्ण की सद्वाणी को इन्कार कर दिया था। यह वही दिल्ली है जहां पुनरावृत्ति हुआ करती है। आपकी सभा वही कौरव की सभा है। आप यहां बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र दो आंखों से नहीं था बल्कि पुत्र के मोह में और सत्ता के मद में अंधा हो गया था। उसकी एक आंख सत्ता के मद से अंधी थी दूसरी पुत्र के मोह में अंधी थी। इसलिए वह सत्य का दर्शन नहीं कर रहा था। आज की सरकार भी सत्ता के नव्द और पुत्र के मोह में अंधी है। उसे भी सत्य के दर्शन नहीं होते हैं। अफसोस इस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे कोई सत्यावादी पराक्रमी पुरुष नहीं है जो, अपनी सरकार के सामने सत्य बात कह सके। अब शकुनि और दुशासन का ही ज्यादा वर्चस्व हो गया है। केवल यहां हा में हां मिलाना आपका कर्तव्य हो गया है। मैं किसी सरकार का खरीदा हुआ नहीं हूं किसी दल का खरीदा हुआ नहीं हूं। भगवान कृष्ण ने उसी कौरव सभा में कहा था कि दुर्योधन याद रखो कि कुल के स्वार्थ के लिये व्यक्ति का बलिदान देना होगा। .. और गांव के स्वार्थ के लिये कुल की बलि दे दो। राष्ट्र के स्वार्थ के लिए गांव की बलि दे दो और आत्मा के कल्याण के लिए राष्ट्र की बलि दे दो। आत्मा सबसे ऊंची है। आत्मा की वाणी सुनों, अन्तरात्मा की अवाज सुनो। आज आप अपनी अन्तरात्मा की आवाज को भूल चुके हो। आप लोगों ने अन्तरात्मा की आवाज पर अपने प्रधान द्वारा दाखिल किये गये मनोनयन के खिलाफ श्री वी० वी०

गिरि को राष्ट्रपति निर्वाचित किया। आज आपकी वह आत्मा कहां मर गई है? आज आप अपनी आत्मा की अवाज को याद करो। राष्ट्र सबसे ऊंचा होता है। हमारी धनमनियों में हमारे पूर्वजों का पवित्र रक्त प्रवाहित हो रहा है। हम गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। याद रखिये हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता, जिसका आप नमक खाते है उसके पैसे से आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उसी हिन्दुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को गलत कामों में फूंक रहे हैं। आज आप जनता को अवाज को सुनिये। जनता का हक जनता को दो। अगर आप जनता को उसके हक नही देंगे तो कौरवों की सभा में जिस तरह से कहा गया था उसी तरह से मैं भी कहना चाहूंगा --

लो दुर्योधन, मैं भी जाता हूं, अंतिम संदेश सुनाता हूं,

याचना नहीं, अब रण होगा जीवन या मरण होगा ।

याद रखिये हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता अपने अधिकारों के लिए झोपड़ियों से निकल रही है। आप हिन्दुस्तान की क्रांति की ज्वाला को नही रोक सकते हैं। आज आप सदन से कह रहे हैं कि हमको भारत की संचित निधि में से पैसा निकालने दो ताकि आप एयासी पर खर्च कर सकों। आपको शर्म आनी चाहिए इस देश में 70 फीसदी से भी अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं इस बजट में आपने कोई पांच छ. हजार करोड़ रुपयों के खर्च का प्रावधान किया है। लेकिन मुझे हैरत यह है कि इस देश की राजधानी दिल्ली में आपने यह स्वीकार किया है कि 227 ऐसे व्यापारी हैं जिन पर एक लाख से ज्यादा बिक्री कर का बकाया है। 12 करोड़ 99 लाख 26 हजार 229 रुपया अकेले इस दिल्ली में बकाया है 227 व्यापारियों ने यह रुपया नहीं दिया है। इस सरकार ने दिल्ली में अपनी नपुंसकता का परिचय दिया है। 227 व्यापारियों पर 13 करोड़ रुपया बिक्री कर का बकाया है। आपने एक प्रश्न में यह स्वयं स्वीकार किया है। ये आंकड़े मेरे घर के आंकड़े नहीं है। गृह राज्य मंत्री श्री लस्कर यहां पर बैठे हुए है, इन्होंने स्वय यह स्वीकार किया है। यह बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। 3 मार्च, 1983 को यह बात स्वीकार की गई है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर जहां 5 लाख 75 हजार 936 गांव है। एक लाख 25 हजार 811 ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख 30 हजार 784 ऐसे गांव हैं जहां पर पेयजल की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान में आधे से भी अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर पर कच्ची पक्की, कोई सड़क नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या अधिकार रह जाता है कि आप संचित निधि में से पैसा निकालें? अभी इस सरकार की स्थिति ऐसी है कि जैसे जान्हुबरात में जब बड़े बड़े बांगे की मंडली जाती है तो नर्तकी भी उस मंडली में होती है और वह उनके आदेश के अनुसार रंगबिरंगी सुर गाती है। उसी प्रकार से आज यह सरकार टाटा, बिरला गोयन्का, सिंघानिया और शांति प्रसाद जैन आदि के इशारें पर नाचती है। बिरला के इशारें पर यह सरकार उन के कारखानों को बढ़ा देती है, टाटा के

[श्री हुक्मदव नारायण यादव]

इशारों पर यह सरकार लोहे के दाम बढ़ा देती है । क्या आप मे हिम्मत है, आप यह 8 करोड 71 लाख रुपया करों का जो बिरला पर बकाया है, इसको वसूल करिये ? 8 करोड़ 85 लाख 56 हजार रुपया टाटा पर बकाया है । 20 लाख 67 हजार रुपया गोयन्का पर बकाया है । है हिम्मत आपमे, आप बिरला, टाटा और गोयन्का से यह रुपया वसूल कर सकेगे ? बिरला, से गोयनका और दिल्ली के व्यापारियो के बकाया वसूल नही करोगे । वह पैसा निकाल कर हिन्दुस्तान के गरीबो के कल्याण पर नही लगाओगे, शिक्षा परनही लगाओगे, पानी पर नही लगाओगे, सडको पर नही लगाओगे और हिन्दुस्तान की करोड़ो जनता के पसीने को चूसोगे अप्रत्यक्ष कर लगाकर, प्रत्यक्ष कर , लगाकर । गावो मे बसने वाले लोगो पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ बढ़ता जा रहा है । महाभारत मे बिदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि राजन माली बाग मे फूल को तोड़ता है, लेकिन पेड़ को जड़ से नही काटता । भवर फूल पर जाता है, उसका रस लेता है लेकिन फूल की सुन्दरता को नहीं बिगाड़ता । राजा का पुनीत कर्त्तव्य है कि जनता से इसी तरह कर वसूल करे और भवरे के समान फूल की सुन्दरता को न बिगाड़े, माली पेड को जड़ से कभी नही काटता। लेकिन आप ऐसे क्रूर माली हो कि फूल की सुदरता को बिगाडते हो, हिन्दुस्तान की जनता जिसके आधे से अधिक लोग दो टाइम रोटी नही पाते, भूखे रहते है, तन पर कपड़े नही है उनसे टैक्स वसूल करने मै आपको शर्म नही आती है । अप्रत्यक्ष कर लगाते हो, चाहे तेल पर हो, चाहे रेल पर हो चाहे बस पर किराया बढ़ाओ अन्य कई तरह से अप्रत्यक्ष कर बढ़ाते हो । इसका सारा बोझ इन करोडो लोगो को उठाना पड़ता है । बिरला के ऊपर टैक्स बकाया है लेकिन उसका आप नहीं वसूल कर सकते हो । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मै आपके स्वय के दिये हुए आकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । 1977–80 मे आपने स्वीकार किया है कि बिरला की सम्पत्ति 34.67 प्रतिशत, टाट की सम्पत्ति 43.77 प्रतिशत, गोयनका की सम्पत्ति मे 56.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मै पूछना चाहता हू कि बिरला की सम्पत्ति में 1970–80 के बीच मे कितनी वृद्धि हुई है, टाटा की सम्पत्ति कितनी बढ़ गई, गोयनका की सम्पत्ति कितनी बढ गई ? सेठो की सम्पत्ति बढ़ती जाती है, उनकी सम्पत्ति आकाश की ओर चली जा रही है और हिन्दुस्तान की करोडों जनता पाताल की ओर चलती जा रही है । सेठों की सम्पत्ति बढ़ती जाती है । हिन्दुस्तान की इस गरीबी के महासागर में कुछ अमीर छोटे-छोटे टापू बनाते जा रहे है और उन टापुओं मे बड़े-बड़े पूजीपतियो के सुन्दरतम महलों का निर्माण करके हिन्दुस्तान की जनता की आखो मे धूल झोंकने का काम आप कर रहे हो । आपने हिन्दुस्तान की करोडों जनता का खून चूसने का काम किया है । हिन्दुस्तान की सरकार, मैं आपसे यह पूछना चाहता हू कि आप इस देश की हुकूमत चलाते हो, पैसा मागते हो, आप इस देश के गरीबों को खाने के लिये क्या देते हो । मैं गाव का रहने वाला साधारण किसान हू । मेरे बाप-दादा ने अपने हाथ से हल चलाकर, भैंस पालकर, खेत की मेंड पर खड़ा होकर अपने जीबन का निर्वाह किया । मैं पूछना चाहता हू कि उन गरीब गांवों मे से लोगों को निकाल कर भारत की संसद् में लाने का काम एक महापुरुष ने किया । इस महापुरुष

के हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब मेरे जैसे ऋणा रहेगे, डा० राम मनोहर लोहिया जिन्होने हम वहा से उठाकर बिहार की विधान सभा मे भेजा और फिर आपको ससद में भेजा, यह उनका काम था । मै आपसे पूछना चाहता हू कि इस देश मे 1979 मे प्रति व्यक्ति प्रति दिन गेहू 129 9 ग्राम मिलता था, 1981 में 130.6 ग्राम गेहू आपने दिया, 1979 मे चावल 200.5 ग्राम मिलता था, 1981 मे 199.2 ग्राम आपने दिया । 1979 मे जहा दाल 44 9 ग्राम मिलती थी, 1981 मे 39.2 ग्राम दिया है । जहा 1979 मे खाद्य तेल 10.4 मिलता था वहा आपका 1980 मे 10.1 ग्राम हो गया । चीनी 79 मे 25 7 ग्राम मिलती थी, 1981 मे 20.0 ग्राम हो गई । दूध जो हिन्दुस्तान की जनता को 1981 के आकड़ों मे 126 ग्राम प्रति दिन मिलता है । मैं पूछना चाहता हू ऐ देश की हुकूमत चलाने वालो, जिस देश मे एक व्यक्ति को 39 ग्राम दाल मिलती हो, हिन्दुस्तान का गरीब प्रोटीन पाता है दाल से, इस देश की गर्भिणी माताये प्रोटीन के अभाव से कमजोर बच्चे पैदा करती है । जो गर्भिणी माताये है, उनको भरपूर मात्रा मे प्रोटीन नहीं मिलता इसलिये उनके जो बच्चे पैदा होते है, जन्म से ही उनकी आखे कमजोर होती है, कान कमजोर होते है, बुद्धि कमजोर होती, तन कमजोर होता है । हिन्दुस्तान की मा के पेट से करोडो बच्चे कमजोर, लुले और लगडे निकल रहे है, कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योकि प्रोटीन नहीं है । गरीबो को प्रोटीन मिलने का एकमात्र सहारा दाल है । लेकिन आप 39 ग्राम प्रति दिन उनको दाल देते हो । चाय के चम्मच से पांच चम्मच दाल हिन्दुस्तान के हर गरीब को आप खाने के लिये देते हो । तब भी आपको शर्म नही आती है । हसते हो, मुस्कराते हो । अभी हसो मुस्कराओ लेकिन एक दिन वह आयेगा जब इन गरीबो के घर से क्राति की लपट निकलेगी । उसमे जल कर राख हो जाओगे झुलस जाओगे उस दिन आपको मेरी बात याद आएगी । कौरवो की सभा मे द्रोपदी की साड़ी खीची जा रही थी सब कौरवो को अपने अहकार मे लज्जा नही आई थी लेकिन जिस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके शरीर को गिद्दो और कौवो ने नोचा था उस दिन कौरवो को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ था। वह दिन आने वाला है याद रखिये । वह दिन दूर नही है। दिन आने वाला है वह मै पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के गरीबों को 11 ग्राम तेल दे कर आप अपने को मजबूत कह रहें है। यह 11ग्राम तेल जिनको आप एक चम्मच तेल दे रहे है, हिन्दुस्तान के गरीबो को 20 ग्राम चीनी दे रहे है चाय के दो चम्मच के बराबर दो चम्मच चीनी है कैसी अच्छी सरकार है यादव जी कैसी अच्छी सरकार है । चीनी देती है दो चम्मच खाद्य तेल देती है एक चम्मच दाल देती है चीनी के चार चम्मच और उस पर इस देश के लोगो को बहादुर और बलवान और मजबूत बनाना चाहते हो सपना देख रहे हो। आपको धिक्कार है। मै आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हू कि इस देश की सरकार ने, मै अपनी बात नही करता आपके ही आंकड़े बोल रहे है कैलोरीज के आधार पर इस देश के गरीबों के स्वास्थ्य का मूल्याकन किया जाए तो वह और हैरत मे पड़ने वाली बात होगी । आपने स्वीकार किया है कि प्रति दिन प्रति व्यक्ति औसत 1940 केलोरीज की पूर्ति होती है। आप क्या खाना उनको दे रही है? 1940कलोरीज देते हैं प्रति व्यवित को स्वस्थ रखने के

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

लिए 10 साल से 18 साल तक के पुरुषो के लिए 2420 कलोरीज की आवश्यकता होती है और आप उनको दे रहे हैं। 1940 कलोरीज । इसी प्रकार से महिलाओं की जिनकी आयु 10 साल से ले कर 18 वर्ष की है उनको कम से कम 2200 कलोरीज स्वस्थ्य रहने के लिए आवश्यकता होती है लेकिन आप उनको दे रहे हैं 1940 कलोरीज, आपके इतनी कलोरीज देने से क्या हिन्दुस्तान का आदमी स्वास्थ्य रहेगा ? वह अस्वस्थ्य, कमजोर और बीमार रहेगा यह आपके आंकड़े बोल रहे हैं इस तरह के आपके आंकड़े हैं। भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद जैसे बड़े बड़े चिकित्सकों की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान के लोगों को स्वास्थ्य रखने के लिए जितनी कलोरीज चाहियें उतनी आप नहीं दे पा रहे हैं फिर आप क्यों अंहकार करते हो ? मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि हरिजन और आदिवासी का आप नाम लेते हैं। मैं आपसे आंकड़े देकर कहना चाहता हूं कि उपसभाध्यक्ष महोदय पटना हाई कोर्ट में क्लास–I में 8 नौकर हैं और उसमें हरिजन और आदिवासी निल है अदर बैकवर्ड क्लोसज निल रिलीजियस माइनार्टीज निल, क्लास–II में 106 आदमी काम करते हैं जिनमें हरिजन 2 आदिवासी 2 और क्लास–III में 468 आदमी काम करते हैं जिनमें हरिजन 28 आदिवासी 7 हरिजन और आदिवासी का नारा देने वाली पटना हाई कोर्ट में जितने जज हैं उन में एक भी न्यायाधीश हरिजन या आदिवासी नहीं है और नही अन्य जगहों पर मिलता है।

आखिर में अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह सरकार संविधान की हत्या करने वाली सरकार हैं। संविधान के प्रति शपथ लेते हो। जब इस सदन में भी हम शपथ लेत है कि संविधान के अनुच्छेद का पालन करेंगे । ईश्वर के नाम पर संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हो लेकिन आपने स्वीकार किया है संविधान का अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हो चुका है परन्तु यह प्राधिकृत अनुवाद संविधान का नही है। संविधान प्राधिकृत, अनुवाद हिन्दी पाठ अधिकृत अनुवाद तैयार कराए जाने से सम्बन्धित पूरा विषय सरकार के विचाराधीन है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह वायदा किया था कि उत्तरोत्तर हिन्दी का विकास होगा और अंग्रेजी निरन्तर नीचे की ओर जाएगी और अंग्रेजी को हम चालू रखेंगे, तब तक चालू रखेंगे जब तक हिन्दी पूरे देश में न पहुंच जाए लेकिन वह संविधान जो हिन्दी को आगे बढ़ाने की गारंटी देता है उस संविधान का आज तक सरकार द्वारा हिन्दी का प्राधिकृत अनुवाद नहीं हो पाया है। आज हिन्दी में यह संविधान हम लें और इसको अगर अदालत में जा कर हिन्दी की मारफत संविधान को रखना चाहें तो उसकी कोई भी प्रमाणिकता नहीं है। वह संविधान हिन्दी में असली है या नकली है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह सरकार जो संचित निधि से पैसा लेना चाहती है यह सरकार न तो किसानों के खेत में पानी दे सकी है न बरोजगारों को काम दे सकी है न भूखों को रोटी दे सकी है न नंगों को कपड़ा दे सकी है इस देश की हुकूमत ने इस देश को नंगा रखा है इस देश को भूखा रखा है इस देश को बेकाम रखा है खेत को बिना पानी का रखा है तन को बिना कपड़े के रखा है मन को भूखा रखने वाली तन को नंगा रखने वाली इस सरकार को एक पैसा भी यह सदन न दे। आप अपने बहुमत के बल पर संचित निधि से पैसा निकाल लोगें, आपका

अधिकार है आपके पास बहुमत है, आपके पास दुशासन है, शकुनी है आपके पास कर्ण जैस लोग है। बहुमत आपका है और बहुमत केबल पर आप संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार प्राप्त कर सकते हो लेकिन इस सदन की मारफत मैं हिन्दुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों का आह्वान करता हूं कि आओं मैं इस सदन का मारफत उन्हें जगाना चाहता हूं कि अब रुकों नहीं :

"आओं श्रमिक, कृषक, मजदूरों
इन्कलाब का नारा दो,
शिक्षक, गुरुजन बुद्धिजीवियों
अनुभव भरा सहारा दो,
फिर हम देखें हम सत्ता
कितनी बर्बर और बडाई है,
तिलक लगाने तुम्हें जवानों
क्रांति द्वार पर आई है।"

हम उस क्रांति के लिए हिन्दुस्तान के करोड़ों जवानों का आह्वान कर रहे हैं कि निकलों आओं सडक पर आओं और अपमान की जिदगी जीने की बनिस्बत, भूखों मरने की बनिस्बत कुत्ते की मौत मरने की बनिस्बत सीने पर गोली खाओं भारत माता की छाती को अपने खून से लाल कर दो लेकिन जुल्मी और अन्यायी की राजसत्ता को आग लगाकर फूंक दो।

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise to support all the three Appropriation Bills that have been moved by the Government for our consideration. Sir, since I spoke on the Railway Budget but did not speak on the General Budget, I take this opportunity to congratulate our young, imaginative and innovative Finance Minister on presenting this wonderfully balanced budget, despite the adverse pressures and constraints created by drought, cyclones and floods in the current financial year. Sir, it is no joke that when inflation is there in almost all other countries, including the developed countries, in our own country the dynamic Government of Mrs. Indira Gandhi has been able to arrest the rate of inflation considerably. During the last one year, as reported in the budget, on the basis of wholesale prices, the rate of inflation comes to only 2 8 per cent and on the basis of the consumer price index, it comes to not more than 8 per cent. It is a real achievement and I congratulate our Government on this achievement.

Sir, in this budget there is no duty on fertilizers any more. Agricultural land has been exempted from estate duty. Even with regard to loans taken by farmers, there is a reduction in the interest rate by one per cent. There is no increase in duty on consumer goods. In fact, on certain items there is a reduction in the excise duty. There is no tax incidence on sugar, about which my friend was just now speaking. The Plan outlay for the rural sector has been increased by 26 per cent in the coming year. So it all speaks highly of the performance of the Government in the current year, that is, 1982-83, and also of the budget proposals put forth by our able Finance Minister. It is, however, our great misfortune that our Opposition friends fail to see good where it is there. They turn a blind eye to all that is good in the performance of the Government. And not only that, they see evil in place of good. That is why our Opposition friends have not been able to find anything good in the performance of our Government during the year 1982-83.

As has already been reported to us, there has been great increase in the production of petroleum in our country. The additional production has been 4 8 million tonnes and it comes to roughly 11,178 tonnes per day, that is, the additional production. The increase in the turnover of the public sector has been 21 per cent. The

[Shri P. N. Sukul]

growth rate in the small industries sector has also been 10 per cent. Under the NREP 330 million additional man-days of rural employment has been generated in the current year. In other words, it means that we gave employment to 9,04,109 persons per day. It is no mean achievement. I am sorry that our friends of the Opposition do not see these things, these good things in our performance.

As regards drinking water facility, it has been extended to 24000 problem villages in the current year. It means taking a year consisting of 365 days, it comes to almost 66 villages per day. So much of drinking facilities we have tried to provide during the current year. Then, additional irrigation potential of 2.35 million hectares has been created during the current year —additional potential. It means an additional potential of 5575 hectares has been created every day in the current financial year.

A lot has been said on various points of the Budget. So I will not take much time of the House in just repeating those things. I will specially congratulate the Government for appointing or for deciding to appoint as Pay Commission for their own employees in the coming year. Very few people have talked about the Pay Commission in this House. But by saying that they would be appointing a Pay Commission, our Government is going to meet a very long-standing demand of its employees. In fact, this Pay Commission should have been appointed by the Janata Government in 1977, 1978, 1979 or 1980. Neither the Janata Government nor the Lok Dal Government appointed a Pay Commission. And during those very years Pay Commissions were appointed by various State Governments to benefit their own employees with the result that because of the revision of the pay scales of the State Government employees, today the pay scales of the State Government employees are better than their counterparts serving the Central Government. That is why I say it has been a very laudable decision. However, in this connection I would like to request our Finance Minister kindly to provide in the very terms of reference of the Commission that the Commission will submit an interim report for providing the much needed interim relief to the employees. It should be provided for in the terms of reference of the Commission. I would also request the Government to appoint representatives of the Government employees on *this Pay Commission. I know it will* be for the first time that the Government will be doing it if they approve of my suggestion. But it is high time that the Government appointed some representatives of the Government employees on the Pay Commission. Also, this Commission should be asked to look into the question of having a national formula of dearness allowance throughout the country. This part has been long neglected and I take this opportunity to impress upon the Government the need for doing this.

As I said at the very beginning, drought has affected almost 48 million hectares of our land in the current financial year. A lot of aid was provided to various State Governments to meet the situation arising out of the drought conditions in those States But I am sorry to say that not a single naya paisa was provided to the Government of Uttar Pradesh for meeting the situation arising out of the drought conditions, not even a single paise... I do not know why. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Now it is only paise, no more naya paise.

SHRI P. N. SUKUL: That is what I say. Our Government demanded more than Rs. 1200 crores to get relief to the people affected by drought. I do not know why and under what circumstances our Central Government has failed to come to the rescue of the

State Government in meeting the situation created by drought. . .

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): Was U.P. not in the list presented by the Minister?

SHRI P. N. SUKUL: That is what I say. The demand was there. Our Government demanded more than Rs. 1200 crores for providing relief to the drought-affected people. Not a single paisa was provided to this biggest State of the Indian Union which was very much badly affected by the drought.

It is indeed very good that our oil production has been increasing year by year. Just a few years back we were importing oil to the extent of about 70 per cent of our import bill. Now, within two years we are supposed to meet 70 per cent of our oil requirements from our own indigenous resources.

Recently there has been a cut in the price of oil which we were importing from the OPEC countries. Because of this cut we are going to save Rs. 450 crores at least. It is true that we have also started exporting crude to various countries including the USA, France, Australia, Spain, etc. And by export of crude we have been able to save about Rs. 1,400 crores worth of foreign exchange in the current financial year. Because of the relief that we are going to get because of the cut in the oil price, I would request the Government to reconsider their decision to levy ten paise on each litre of kerosene oil. Others, from both sides, have also made this suggestion. It is the people below the poverty line who use kerosene oil generally. When the Government have already given so much subsidy on various items meant for the poor, it will be entirely in the fitness of things if our Government reconsider this levy of ten paise on each litre of kerosene oil. If they are not in a position to do this, at least they should make it five paise. Not more than five paise should be charged extra on each litre of kerosene oil.

As I said, I am not going to take much of your time. With these words, I support the three Appropriation Bills that have been moved for our consideration. I will request the Government to consider the four or five suggestions that I have made just now. I hope the House will pass all these appropriation Bills unequivocally.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Would Dr. Adiseshiah like to start his speech?

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Mr. Vice-Chairman; as I supported the Union Budget on the basis of its strength outweighing its weaknesses, which I listed on both sides, I have no hesitation in supporting the Appropriation (Vote on Account) Bill for 1983-84. I am also supporting somewhat reluctantly the other two Appropriation Bills, namely, the Appropriation Bill for last year, 1982-83 which really amounts to supplementary demand and the Appropriation (No. 2) Bill, 1983, which is for the period of 1980-81. I have some comments which I will make on why I give my reluctant support.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Now we will take up the Half-an-Hour Discussion.

SHRI P. N. SUKUL: How long are we sitting?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): If we finish this early, then Dr. Adiseshiah can continue his speech.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Not now. I will speak tomorrow.

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन्) : कल करेंगे फिर हाफ-एन-अवर के बाद हाउस एडजर्न होगा ।